

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के ऑल इंडिया डिजिटल लॉन्च  
माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चन्द कटारिया जी का अभिभाषण

दिनांक : 20 फरवरी 2024, मंगलवार

समय : 11.30 PM

स्थान : कॉटन विश्वविद्यालय

- असम सरकार के शिक्षा मंत्री डॉ. रनोज पेगू जी,
- कॉटन यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. रमेश चंद्र डेका जी,
- संकाय के रजिस्ट्रार, डीन, प्राध्यापक एवं अधिकारी गण
- उपस्थित मेरे प्यारे विद्यार्थियों

आप सभी को मेरा नमस्कार !

देश भर में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के डिजिटल लॉन्च के कार्यक्रम में आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे गर्व हो रहा है। यह खुशी की बात है कि भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने मल्टीडिसिप्लिनेरी एडुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (MERU) योजना के अंतर्गत डिब्रुगढ़ विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए और कॉटन विश्वविद्यालय एवं बोड़ोलैंड विश्वविद्यालय को 20-20 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। इसके लिए मैं असम के तीनों उच्च शिक्षण संस्थानों को बधाई देता हूं। साथ ही केंद्र सरकार को हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

मुझे यह जानकार अति प्रसन्नता हुई कि इस परियोजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर के तीन अन्य राज्यों त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और सिक्किम के कंचनजंगा स्टेट यूनिवर्सिटी को भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 20-20 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया गया। मैं इन विश्वविद्यालयों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि केंद्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण कदम से पूर्वोत्तर के इन उच्च शिक्षण संस्थानों के बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। मेरा यह भी विश्वास है कि ये सभी उच्च शिक्षण संस्थान केंद्र सरकार की इस सहायता का पूर्ण लाभ उठाएंगी और पूर्वोत्तर में उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में सकारात्मक सोच, समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ काम करेंगी।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार पूर्वोत्तर के विकास में अधिक जोर दिया है। सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्यों में न सिर्फ परिवहन और संचार पर विशेष ध्यान दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष ध्यान दिया है।

देवियों और सज्जनों,

केंद्र सरकार देश के विकास के लिए एक अभियान के रूप में काम कर रही है। सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की नीति पर काम कर रही है। देश में बिना किसी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय और क्षेत्र के भेदभाव के सर्वस्पर्शी और सर्व-समावेशी विकास हुआ है।

शिक्षा के माध्यम से लोगों में देश के विकास के लिए जागरूक, प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए सरकार का देश में परिवहन, सीमा सुरक्षा, सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में विकास के साथ-साथ शिक्षा क्षेत्र के विकास में पर जोर रहा है। सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, नवोन्मेष और शोध को बढ़ावा देने और देश को पुनः ज्ञान का सुपर पावर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति को लागू किया है।

नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसके क्रियान्वयन पर पूरा जोर दे रही है। सरकार विशेषज्ञों, शिक्षकों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों के सहयोग से एनईपी 2020 के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए पूरी ताकत के साथ काम रही है।

इसी क्रम में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) परियोजना को आज देश भर में शुरू किया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि यह शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, नवोन्मेष और शोध को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक के रूप में काम करेगी। इस परियोजना के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्त पोषित किया जा रहा है, ताकि इन संस्थानों में शिक्षा के बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और विकास सुनिश्चित हो सके। साथ ही उच्च शिक्षा प्रणाली में उच्च स्तर की पहुंच, समानता और उत्कृष्टता भी प्राप्त किया जा सके।

पहले यह परियोजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के नाम से जाना जाता था। इसे पहले वर्ष 2013 में लान्च किया गया और 2018 में इसका दूसरा चरण शुरू हुआ। इन दो चरणों में RUSA के अंतर्गत सुविधाओं में सुधार और विकास के लिए करीब 2500 शिक्षण संस्थानों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इससे संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात (GER) और गुणवत्ता सुधार, छात्र-शिक्षक अनुपात आदि जैसे कई उच्च शैक्षिक संकेतकों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

अब यह परियोजना नए नाम “प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान” से लॉन्च किया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि यह परियोजना पहले से और अधिक प्रभावी और व्यापक रूप से लागू होगा और देश में उच्च शिक्षा की दशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यह अभियान भारत के राज्य विश्वविद्यालयों के विशाल नेटवर्क की क्षमता विकसित करने के लिए संघीय सरकार की पहल है। देश का भविष्य इन संस्थानों को छात्रों के सीखने के परिणामों, विकास और नवीन सोच में सुधार के लिए आवश्यक सभी चीजों से लैस करने पर निर्भर करता है।

भारत सरकार राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के मूल्य को बढ़ाने के साथ-साथ उनके मौजूदा कौशल को मजबूत करना चाहती है, ताकि वे मांग-संचालित, जीवंत, उत्पादक और गुणवत्ता के प्रति जागरूक बन सकें। यह पहल इस बात पर जोर देती है कि प्रत्येक संस्थान शीर्ष पायदान की शिक्षा के माध्यम से जीवन को लाभान्वित कर सकता है।

देवियो एवं सज्जनों,

काँटन यूनिवर्सिटी असम में उच्च शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान है। काँटन विश्वविद्यालय अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुझे खुशी है कि काँटन विश्वविद्यालय ने पीएम-उषा के अंतर्गत अनुदान पाने के लिए आवश्यक मापदंडों को पूरा करने में सफल रहा। मेरा विश्वास है कि केंद्र सरकार के इस अनुदान से काँटन यूनिवर्सिटी के विभिन्न शैक्षणिक और केंद्रित पहलों में तेजी आएगी।

अंत में मैं पुनः प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत अनुदान पाने के लिए काँटन यूनिवर्सिटी सहित पूर्वोत्तर के अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को बधाई देता हूँ और भविष्य के कार्यों के शुभकामनाएं देता हूँ।

धन्यवाद।

जय हिन्द।